

प्रेषक,

प्रेम सिंह खिमाल,  
अपर सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महाधिवक्ता,  
उत्तराखण्ड,  
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,  
नैनीताल।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 17 जनवरी, 2013

विषय- महाधिवक्ता कार्यालय, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में 10 पद आशुलिपिक, संविदा/आउटसोर्सिंग से रखे जाने की स्वीकृति प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-474/P.S./2012 दिनांक 18-10-2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महाधिवक्ता कार्यालय, नैनीताल में आशुलिपिक, संविदा/आउटसोर्सिंग के 10 पदों पर समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-596/XVII-3/2011-09(17)/2004 दिनांक 18.11.2011 में उल्लिखित दरों एवं शर्तों पर अग्रिम आदेशों तक रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त पद धारक को शासनादेश दिनांक 18.11.2011 द्वारा प्रदत्त सुविधायें अनुमन्य होगी।

4- उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप नियुक्ति होने के उपरान्त होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या 04 के लेखाशीर्षक "2014 न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)-03-महाधिवक्ता-00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नाम डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0- 140 NP/XXVII(5)/2012 दिनांक 14.01.2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रेम सिंह खिमाल)  
अपर सचिव

क्रमश.....2

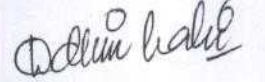
*(Handwritten signature)*

संख्या- 22(1)/ XXXVI(1)/2013 -160/2010 तददिनांकित

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा देहरादून।
- 2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
- 3- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से



(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)  
संयुक्त सचिव